बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

ल.अं./46/एसएलबीसी/मार्च 2020/340

19.05.2020

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0 प्र0) के समस्त सदस्यों को पत्र

महोदय/महोदया,

विषय :- राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ.प्र.) की मार्च 2020 हेतु समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

कृपया राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ. प्र.) की त्रैमासान्त **मार्च 2020** को समाप्त तिमाही हेतु आयोजित बैठक दिनांक 05.05.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस क्रम में उपरोक्त बैठक का कार्यवृत्त आपकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है। हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि संलग्न कार्यवृत्त को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0 प्र0) की वेबसाइट www.slbcup.com पर अपलोड कर दिया गया है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया विभिन्न कार्य बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अद्यतन प्रगति हमें प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि तदनुसार आगामी बैठक में इसका समावेश किया जा सके।

भवदीय,

(बलबीर सिंह लुथरा)

उप महाप्रबन्धक

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0 प्र0)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.), अंचल कार्यालय, लखनऊ अंचल, "बड़ौदा हाउस", वी–23, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226 010
State Level Bankers' Committee (U.P.), Zonal Office, Lucknow Zone, "Baroda House", V-23, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226 010
फोन / Phone : 6677607 (GM), 6677609 (Sectt.), 6677722 (DGM), 6677721, 6677694 (DEPTT.)
ई–मेल / E-mail : slbc.up@bankofbaroda.co.in वेबसाइट / Website : www.slbcup.com

राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ. प्र.) की मार्च 2020 तिमाही की बैठक दिनांक 05.05.2020 का कार्यवृत्त

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की प्रत्येक त्रैमासांत की बैठक आगामी त्रैमास के अंत तक नियमित रूप से आयोजित किये जाने का प्रावधान है। इसी क्रम में कोविड -19 महामारी के दृष्टिगत मार्च 2020 त्रैमास की बैठक 05.05.2020 को संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उ0 प्र0 द्वारा अनुमोदित सहभिगा सूची के अनुसार चयनित सहभागियों के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय, लखनऊ में सम्पन्न की गयी ताकि बैठक के दौरान "सामाजिक दूरी" का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। शेष सभी सदस्यों को एजेण्डा पुस्तिका ई-मेल द्वारा प्रेषित कर उनसे प्राप्त सुझावों व संशोधनों को कार्यवृत्त में शामिल किया जा रहा है।

बैठक की अध्यक्षता श्री विक्रमादित्य सिंह खीची, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा वीडियो कॉनफ्रेंसिंग द्वारा की गयी। इस बैठक में प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी श्री संजीव मित्तल, आई.ए.एस., अपर मुख्य सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन; प्रमुख सचिव, एम.एस.एम.ई.; श्री शिव सिंह यादव, महानिदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उ0प्र0; अन्य विभागों के प्रमुख सचिव; श्री आर० लक्ष्मीकांत राव, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ; श्री शंकर ए० पाण्डेय, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड; की उपस्थिति प्रमुख रही। साथ ही विभिन्न बैंको/वित्तीय संस्थाओ के वरिष्ठ कार्यपालकों तथा राज्य व केन्द्र सरकार के उच्चाधिकारियों ने भी इस बैठक मे सहभागिता की। बैठक मे भाग लेने वाले सहभागियों की सूची संलग्न है।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 30.03.2020 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि
Confirmation of Minutes of Last SLBC Meeting dated 30.03.2020 (Through Agenda By Circulation)

दिसम्बर 2019 त्रैमासांत की "Agenda By Circulation" के माध्यम से सम्पन्न बैठक दिनांक 30.03.2020 के कार्यबिन्दु एवं कार्यवृत्त सभी सदस्यों को एस.एल.बी.सी. के पत्रांक ल.अ./46/दिसम्बर 2019/213 दिनांक 06.04.2020 के माध्यम से प्रेषित किये गये थे, जिसकी पुष्टि समिति द्वारा की गयी। उक्त कार्यवृत्त में समस्त सम्बन्धित से प्राप्त सुझावों/ संसोधन को सम्मिलित किया गया है |

बैठक के प्रारम्भ में डॉ0 रामजस यादव, मुख्य महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0 प्र0) ने आभार प्रकट करते हुए सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने प्रदेश में गत तिमाही के दौरान बैंकों द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण मानकों पर प्रदेश की स्थिति संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए बताया कि प्रदेश में बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों हेतु निर्धारित मानकों को पार कर अच्छी उपलब्धि हासिल की गयी है व वार्षिक ऋण योजना में भी गत वर्ष के सापेक्ष 15% की वृद्धि दर्ज करते हुए रू.200855 करोड़ की स्वीकृति के साथ ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की गयी है। 450605 खातों में CGTMSE सुविधा प्रदान करते हुए हमारा प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है। कोविड-19 महामारी के दौरान प्रदेश सरकार के सहयोग से 18937 बैंक शाखाओं व 63179 बैंक मित्रों (औसतन एक बैंकिंग आउटलेट प्रति 2.96 वर्ग कि.मी.) द्वारा जन सामान्य तक बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने सभा में उपस्थित बैंकर्स साथियों से निम्नवत अनुरोध किया:-

- 14 मई, 2020 को प्रस्तावित **"ऑनलाइन रोज़गार संगम"** में दो लाभार्थी प्रति शाखा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस हेतु समस्त बैंकों का सहयोग अपेक्षित है। **(कार्यवाही: समस्त बैंक)**
- पी.एम.किसान लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड से संतृप्त करने हेतु कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित अभियान के अंतर्गत सैद्धांतिक (In-principle) रूप से स्वीकृत आवेदनों को 1 सप्ताह के भीतर निस्तारित करने की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु समस्त बैंकों से अनुरोध किया। **(कार्यवाही: समस्त बैंक)**

अंत में उन्होंने प्रदेश सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, शासन के विभिन्न विभाग, नाबर्ड, बैंकों व अन्य संस्थाओं द्वारा कोविड-19 की कठिन परिस्थितियों में प्रदान किये जा रहे सहयोग व बैठक में सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन मे श्री विक्रमादित्य सिंह खीची, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सभी सदस्यों का अभिवादन करते हुये वैश्विक, देश एवं प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों तथा विभिन्न मानकों में प्रदेश मे दर्ज प्रगति से समिति को अवगत कराया। उन्होंने राज्य की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने तथा इसे नई ऊंचाइयों तक पहुँचाने मे बैंकों द्वारा प्रदान सहयोग की सराहना करते हुए निम्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला :

- प्रदेश का ऋण जमानुपात मार्च 2020 को समाप्त तिमाही में 52% के स्तर पर है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सभी बैंकों की जमा राशि रू. 10.12 लाख करोड़ँ (मार्च 2019) के स्तर से बढकर रू. 11.39 लाख करोड़ (मार्च 2019) को पार कर गयी है जो लगभग 12.55% (1.27 लाख करोड़) की वृद्धि दर्शाती है।
- मार्च 2019 के अग्रिम रू. 5.43 लाख करोड़ में भी रू. 44000 करोड़ की वृद्धि दर्ज करते हुए मार्च 2020 में कुल अग्रिम रू. 5.87 लाख करोड़ के स्तर तक पहुँच चुका है।
- मार्च 2020 तक कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अग्रिम रू 3.49 लाख करोड़ रहा है जो कि कुल अग्रिम का 59% है ,इसी के साथ प्राथमिकता क्षेत्र, अग्रिमों के 40% के Benchmark को पार कर गया है।
- देश का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य होने के नाते, प्रदेश में वित्तीय समावेशन गतिविधियों की पर्याप्त सम्भावनाएँ है। हमारा प्रदेश प्रधान मंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत 6.13 करोड़ खातों (रू. 22598 करोड़) के साथ PAN INDIA प्रथम स्थान पर है। PMJDY खातों में कुल जमा राशि में गत वर्ष की तुलना में 27.75% की वृद्धि दर्ज हुई है।
- अटल पेंशन योजना (APY) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य में कुल 9.90 लाख नये नामांकन करते हुए प्रदेश में ग्राहकों की संख्या 32.42 लाख के स्तर पर पहुँच गई है। मुझे यह अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि PFRDA द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान APY के अंतर्गत अधिकतम नामांकन करने हेतु एस.एल.बी.सी. (उ0प्र0) को देश की सर्वश्रेष्ठ एस.एल.बी.सी. के सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत हमारा प्रदेश 253 लाख व 65 लाख नामांकन के साथ पूरे भारतवर्ष में क्रमशः प्रथम व दूसरे स्थान पर है।
- दिनांक 04.02.2019 को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समस्त किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से संतृप्त करने के उद्देश्य से शुरू की गयी "KCC Saturation Drive" के अंतर्गत बैंकर्स तथा प्रदेश सरकार के सहयोग से कुल 26.51 लाख के.सी.सी. स्वीकृत करते हुए हमारा प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
- माननीय प्रधानमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में जनपद वाराणसी में MSME उद्यमियों हेतु फरवरी माह में एक मेगा कैम्प का आयोजन किया गया। हर्ष का विषय है कि प्रदेश सरकार व सभी बैंकों के संयुक्त प्रयासों से कैम्प के दौरान MSME क्षेत्र के अंतर्गत कुल रु 5061 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया।
- प्रदेश द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजनांतर्गत आवंटित कुल 19534 करोड़ लक्ष्यों के सापेक्ष रु 23867 करोड़ का ऋण वितरण करते हुए लक्ष्यों को हासिल कर लिया गया। उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य ने इस योजना के तहत संवितरण के मामले में सबसे अधिक संख्या हासिल की है।
- भारत सरकार द्वारा "Less Cash" अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए डिजिटलीकरण को मुख्य रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में मार्च 2020 में कुल Digital Transactions 189.07 करोड़ (संख्या) के स्तर पर पहुँच गया है जो मार्च 2019 के कुल Transaction 161.68 करोड़ की तुलना में 27.39 करोड़ अधिक है।
- प्रदेश में एक वर्ष के भीतर डीजिटल भुगतान के साधनों का विस्तार करने हेतु Adopt किये गये दो जनपदों यथा Firozabad और Siddhartha Nagar (Aspirational District) में बैंकों को लक्ष्यों का आवंटन किया जा चुका है। सभी बैंकों से अनुरोध है कि वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु इन जनपदों में आवश्यक सहयोग प्रदान करें। **(कार्यवाही: समस्त बैंक)**
- प्रदेश में विभिन्न सरकार प्रायोजित योजनाएँ यथा PMEGP, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, कौशल विकास कार्यक्रम, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, स्वयं सहायता समूह (SHG) आदि संचालित की जा रही है जो राज्य में रोजगार के अवसर प्रदान करने के राज्य व राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति में एक अहम भूमिका निभायेगी।

- बैंको द्वारा प्रदेश सरकार की पहल से स्थापित Mega Infrastructure Projects जैसे Express way, Airports, मेट्रो रेल, Defence Industrial Corridor आदि की स्थापना में सक्रिय रूप से भाग लिया जा रहा है।
- NPA में लगातार वृद्धि बैंकर्स के लिए चिंता का विषय है क्योंकि यह बैंक की तरलता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। वर्तमान एन.पी.ए. स्तर कुल 11.81% की वृद्धि दर्शाते हुए रू. 44860 करोड़ (मार्च 2019) से बढकर रू. 50160 करोड़ (मार्च 2020) तक पहुँच गया है। साथ ही कुल 10.28 लाख वसूली प्रमाण पत्र (रू.9306 करोड़) तहसील स्तर पर वसूली हेतु लम्बित हैं जिसमें से 6.25 लाख खाते (रू. 5147 करोड़) एक वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित हैं। सरफेसी एक्ट के अंतर्गत जिलाधिकारी की अनुमति हेतु लम्बित मामले डेढ गुना वृद्धि दर्ज करते हुए इनकी संख्या लगभग 3522 खाते (रू. 2282 करोड़) से बढकर 5262 खाते (रू. 2637 करोड़) हो गयी है। बैंक बकायों की वसूली हेतु राज्य सरकार के द्वारा दिए जा रहे सहयोग की सराहना करते हुए उन्होंने भविष्य में हमें बेहतर सहयोग प्रदान करने हेतु अनुरोध किया।

(कार्यवाही: संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उ0 प्र0)

देश भर में लॉकडाउन के दौरान अवकाशों पर भी अत्यंत सावधानी और समर्पण के साथ बैंकिंग सुविधा प्रदान करने हेतु बैंकर्स साथियों का आभार व्यक्त किया व भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप – Emergency Line of Credit (COVID-19) के माध्यम से समाज को आवश्यक ऋण सहायता प्रदान करने हेतु आश्वासन दिया। अंत में बैठक में पधारे सभी गनमान्य अतिथियों की सक्रिय भागीदारी हेतु हृदय से आभार व्यक्त करते हुए सुरक्षित व स्वस्थ रहने का संदेश दिया।

श्री आर. लक्ष्मीकांत राव, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ ने सभा में उपस्थित समस्त अतिथियों का अभिवादन करते हुए हर्ष व्यक्त किया कि कोविड-19 महामारी के दौर में प्रदेश में बैंकों द्वारा निर्बाध रूप से आमजन को बैंकोंग सुविधाएं प्राप्त हो रही है तथा प्रदेश सरकार का भरपूर सहयोग बैंकों को प्राप्त हो रहा है। तत्क्रम में उन्होंने निम्नानुसार सभा को सम्बोधित किया:-

- भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत कृषि ऋण की समीक्षा हेतु गठित आंतरिक कार्य समूह (IWG) द्वारा पारदर्शिता और एकरूपता लाने के उद्देश्य से फसलों व संबद्ध कृषि गतिविधियों, अर्थात पोल्ट्री, डेयरी, आदि हेतु राज्य स्तर पर Scale of Finance (SoF) निर्धारित करने का सुझाव दिया गया था जिसे नाबार्ड द्वारा अन्य हितधारकों से परामर्श के उपरांत मान्य कर लिया गया है। इसी क्रम में नाबार्ड के परिपत्र दिनांक 15.04.2020 द्वारा संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं जिसके अनुसार जिला स्तरीय तकनीकी समितियों (DLTCs) द्वारा प्रेषित इनपुट के आधार पर राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) द्वारा विभिन्न मानकों यथा कृषि जलवायु क्षेत्रों, फसल पैटर्न, कृषि प्रथाओं और बढ़ती परिस्थितियों आदि को ध्यान में रखते हुए राज्य में सभी फसलों (बागवानी फसलें, पशुपालन और मत्स्य पालन आदि सहित) हेतु SoF को अंतिम रूप दिया जाएगा तथा विस्तृत अधिसूचना जारी की जाएगी।
- एक वर्ष में पूर्ण रूप से डिजिटल पेमेंट प्रणाली लागू करने हेतु चयनित प्रदेश के 2 जनपदों यथा फिरोज़ाबाद व सिद्धार्थनगर (अग्रणी बैंक-भारतीय स्टेट बैंक) में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रगति की समीक्षा की गयी है तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0प्र0) को इन जनपदों में अक्टूबर 2020 तक लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु समयबद्ध रोडमैप तैयार करने हेतु भी आवश्यक दिशा-निदेश जारी किये गये हैं। इस उद्देश्य हेतु केनरा बैंक के समंवय में गठित उपसमिति व इन जनपदों में कार्यरत समस्त बैंकों द्वारा विशेष ध्यान व प्रयास की आवश्यकता है।

(कार्यवाही: केनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एस.एल.बी.सी., तथा चयनित जनपदों में कार्यरत समस्त बैंक)

- उन्होंने अवगत कराया कि वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति (NSFI):2019-24 में हाउसहोल्ड तक बैंकिंग सुविधाए पहुँचाने हेतु विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही जन सामान्य तक बैंकिंग सुविधाएं पहुँचाने में बैंक मित्रों की अहम भूमिका व योगदान को ध्यान में रखते हुए उनकी कार्य क्षमता के निर्माण हेतु भी आवश्यक कदम उठाए जाने हैं। इसी क्रम में माह नवम्बर 2019 में बैंकों हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा "Train the Trainers Programme for Capacity Building of Business Correspondents" कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया था।

BANK OF BARODA ZONAL OFF (LUCKNOW) अंचल कार्यालय

➢ वार्षिक ऋण योजना 2019-20 के अंतर्गत कृषि और सेवा क्षेत्र के लक्ष्यों के सापेक्ष शत प्रतिशत उपलब्धि नहीं हुई है। वार्षिक क्रेडिट योजना 2020-21 के लक्ष्य निर्धारण के विषय पर उन्होंने बताया कि वर्तमान प्रणाली में Potential Linked Plan (PLP) के गत वर्षों के लक्ष्यों में 10-12% की वृद्धि के आधार पर चालू वित्तीय वर्ष हेतु PLP व वार्षिक क्रेडिट योजना (ACP) निर्धारित की जाती है। उन्होंने सुझाव दिया कि ACP के लक्ष्यों का निर्धारण गत वर्ष की उपलब्धि में वृद्धि के आधार पर किया जाना चाहिए ताकि प्राप्य व उचित लक्ष्यों को प्रदेश द्वारा हासिल किया जा सके। उन्होंने नाबार्ड व अन्य बैंकों से इस विषय पर विचार करने हेतु सलाह दी।

➢ प्रदेश के ऋण जमानुपात में समस्त बैंकों के सहयोग से सुधार की आवश्यकता है।

(कार्यवाही: समस्त बैंक व यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया)

➢ प्रदेश के एन.पी.ए. स्तर में बद्धोत्तरी हुई है व आर.सी. लम्बित मामलों की संख्या बढी है, जो चिंता का विषय है व प्रदेश सरकार से आवश्यक सहयोग की अपेक्षा है। उन्होंने बैंकों से सबसे अधिक आर.सी. लम्बित मामलों वाले 10 जनपदों की सूची राजस्व विभाग, उ0 प्र0 को प्रदान करने हेतु अनुरोध किया। **(कार्यवाही: समस्त बैंक)**

श्री शंकर पांडे, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, ने अपने सम्बोधन में सर्वप्रथम प्रदेश के समस्त बैंक कर्मचारियों की लॉकडाउन के दौरान "Front Line Warriors" के रूप में कार्य करने के लिए सराहना की जिनके माध्यम भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी सहायता राशि व अन्य बैंकिंग सुविधाओं को जन सामान्य तक पहुँचाना सम्भव हो सका है। इसके उपरांत उन्होंने निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला:-

➢ कोविड-19 के चलते भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित Special Liquidity Facility (SLF) के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों व कोऑपरेटिव बैंकों को रू. 1400 करोड़ की राशि स्वीकृत व वितरित कर दी गयी है तथा NBFC-MFI हेतु भी इस सुविधा हेतु विचार किया जा रहा है।

➢ लॉकडाउन के दौरान नाबार्ड द्वारा स्वीकृत 57 मोबाइल वैन (ए.टी.एम. सहित), स्वयं सहायता समूहों, बैंक मित्रों, किसान उत्पादक संगठन आदि द्वारा प्रदेश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक सेवायें यथा बैंकिंग सुविधाएं, मास्क, खाद्यान्न आदि मुहैया कराये जा रहे हैं। **उन्होंने बैंकों से ग्रामीण क्षेत्रों में Infrastructure को अधिक सुद्रढ व स्वयं सहायता समूहों को अधिकाधिक वित्त पोषित करने हेतु अनुरोध किया।**

➢ नाबार्ड द्वारा उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम को 40 गोदामों के निर्माण की परियोजना हेतु रू.146 करोड की राशि स्वीकृत की गयी है जो सरकार द्वारा नियोजित अतिरिक्त गेहूं खरीद के भंडारण में उपयोगी होगी।

➢ 2019-20 के दौरान बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में वार्षिक रण योजनांतर्गत आवंटित लक्ष्य रू. 1.70 लाख करोड के सापेक्ष कुल रू. 1.17 लाख करोड़ की स्वीक्रति की गयी जो आवंटित लक्ष्यों का 69% है। **उन्होंने बैंकों को सभी PM_KISAN लाभार्थियों की संतृप्ति हेतु किसानों को KCC प्रदान करने पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी।** MSME के तहत सभी बैंकों द्वारा बेहतरीन कार्य करते हुए रू. 0.71 लाख करोड़ ऋण की स्वीकृति की गयी जो आवंटित लक्ष्यों का 137% है।

➢ उन्होंने बताया कि Potential Linked Plan 2020-21 में कुल रू. 2.95 लाख करोड़ की अनुमानित क्रेडिट क्षमता है। कृषि के तहत 1.94 लाख करोड़ (1.39 लाख करोड़ के फसल ऋण सहित) का उच्च ऋण प्रवाह भारत सरकार के 2022 तक कृषकों की आय को दोगुना करने के आशय से योजित किया गया है जिसमें राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा **केसीसी संतृप्तिकरण** के को पूरा करने के लिए आवश्यक वृद्धिशील ऋण प्रवाह को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने वार्षिक ऋण योजनांतर्गत कृषि हेतु लक्षित ऋण प्रवाह को प्राप्त करने के लिए बैंकों से भी अपील की।

➢ नाबार्ड द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक व नाबार्ड के दिशा-निर्देशों के क्रम में Scale of Finance तय करने के निर्देश जारी किये गये हैं तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0प्र0) से अनुरोध है कि Scale of Finance के पुनरीक्षण हेतु प्रदेश के समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धकों को डी.एल.टी.सी. की बैठकें सम्पन्न कराने हेतु निर्देशित करें ताकि राज्य स्तरीय तकनीकी समिति में अंतिम अनुमोदन हेतु उन्हें प्रेषित किया जा सके। **(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0 प्र0) व समस्त अग्रणी बैंक)**

➢ श्री पाण्डे द्वारा सभा को अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में नाबार्ड द्वारा प्रदेश सरकार एवं बैंकों को रू.12022 करोड़ के साथ-साथ अन्य संस्थाओं को भी रू. 25 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है।

श्री नवनीत सहगल, आई.ए.एस., प्रमुख सचिव, एम.एस.एम.ई., उत्तर प्रदेश शासन ने अपने सम्बोधन में सभा के समक्ष निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला:-

- उन्होंने अवगत कराया कि प्रदेश में देश के लगभग 15% एम.एस.एम.ई. संचालित है जिन्हें कोविड-19 महामारी के चलते वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत एक बड़ी जनसंख्या बेरोज़गार हो रही है। आगामी माह जून 2020 इस क्षेत्र हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी कोविड-19 पैकेज के अंतर्गत एम.एस.एम.ई. क्षेत्र हेतु घोषित राहत व सुविधाएं निश्चय ही इनकी गतिविधियाँ शुरू करने में सहायक सिद्ध होगी। इसी क्रम में प्रदेश शासन द्वारा भी एक पोर्टल **"एम.एस.एम.ई.साथी"** का विमोचन किया जा रहा है जिसमें विभिन्न एम.एस.एम.ई. उद्यमी अपनी परेशानियाँ व प्रश्न बैंकों के समक्ष ऑनलाइन मोड से रख सकते हैं ताकि उनका शीघ्रता से निस्तारण हो सके। ये सभी प्रयास एम.एस.एम.ई. उद्यमों को संचालित कर प्रवासी श्रमिकों को रोज़गार उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होंगे।
- यद्यपि वार्षिक ऋण योजनांतर्गत बैंकों द्वारा 2019-20 में एम.एस.एम.ई. के लक्ष्यों को हासिल किया गया है, समस्त बैंकों से अनुरोध है कि वे लॉकडाउन के इस दौर में अधिक से अधिक उद्यमियों को ऋण प्रदान करने का प्रयास करें जिससे भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र हेतु आवंटित वित्तीय सहायता राशि का पूर्ण रूप से उपयोग हो सके।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

- लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों को स्वतः रोज़गार प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा योजना तैयार की जा रही है। इसी के तहत एक **"ऑनलाइन रोज़गार संगम"** का आयोजन किया जा रहा है जिसमें विभिन्न केन्द्र व राज्य सरकार प्रायोजित योजनाओं के तहत आवेदकों को विशेषकर वित्तीय वर्ष 2019-20 की मार्च तिमाही में स्वीकृत/स्वीकृति हेतु लम्बित आवेदन पत्रों के सापेक्ष बैंकों द्वारा लगभग रू. 2-3 हज़ार करोड़ की ऋण राशि प्रदान की जानी है।
- बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैण्ड अप इण्डिया, स्टार्ट अप इण्डिया योजना के ऐसे लाभार्थी जो "एक जनपद एक उत्पाद" योजना हेतु पात्र हैं, उन्हें इस योजना से जोड़ा जाना चाहिए ताकि उन्हें दोनों योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता का लाभ प्राप्त हो सके।
- प्रदेश सरकार द्वारा माटीकला उद्योग से जुड़े कुम्हार व अन्य श्रमिकों हेतु एक नयीमार्जिन मनी योजना संचालित की जा रही है जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष 300 श्रमिकों को योजना के अंतर्गत लाभांवित करने का लक्ष्य तय किया गया है। समस्त बैंकों द्वारा इस योजना के सफल संचालन हेतु आवश्यक सहयोग की अपेक्षा है।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

अंत में उन्होंने लॉकडाउन के दौरान समस्त लाभार्थियों, आमजन व प्रदेश सरकार को सहयोग प्रदान करने हेतु प्रदेश में कार्यरत समस्त बैंकों को धन्यवाद दिया व आगामी **"ऑनलाइन रोज़गार संगम"** व अन्य एम.एस.एम.ई. योजनाओं में बैंकों के सहयोग हेतु अनुरोध किया।

श्री संजीव मित्तल, आई.ए.एस., अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त, उत्तर प्रदेश शासन ने अपने सम्बोधन में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0प्र0) को सर्वश्रेष्ठ राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति घोषित किये जाने हेतु बधाई दी व अपेक्षा की कि भविष्य में भी प्रदेश में बैंकों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी रहेगा। तत्पश्चात उन्होनें प्रदेश के विकास के विभिन्न मानकों व विषयों पर निम्नानुसार प्रकाश डाला:-

- कोविड-19 महामारी ने प्रदेश के जनसमूह सहित राजस्व विभाग व प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है। साथ ही इन परिस्थितियों के चलते बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक प्रदेश में वापस लौट रहे हैं जिन्हें रोज़गार प्रदान करना प्रदेश सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस हेतु प्रदेश में बैंकों की महती भूमिका रहेगी तथा शासन के विभिन्न विभागों द्वारा उठाए गये कदमों व योजनाओं में बैंकों द्वारा सक्रिय सहभागिता व सहयोग हेतु आह्वान किया।

- हमारे प्रदेश में भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गयी सहायता राशि का लाभ सबसे अधिक लाभार्थियों तक पहुँचाया गया है। इसी तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा भी एक राहत पैकेज घोषित किया गया था जिसके अंतर्गत 3 करोड़ लाभार्थियों को प्रति माह रू.1000 की सहायता राशि प्रदान की जानी है। योजना की प्रथम किश्त माह अप्रैल 2020 में प्रदान की जा चुकी है। कई मनरेगा/ अंत्योदय आदि श्रेणी के श्रमिकों को राशन व अन्य राहत सामग्री मुफ्त/सस्ते दामों पर प्रदान की जा रही है।
- प्रदेश के ऐसे 36 जनपदों, जिनका ऋण जमानुपात 50% से कम है, में बैंकों द्वारा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
- **वित्तीय सेवायें विभाग, भारत सरकार द्वारा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से संतृप्त करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं जिसके अंतर्गत प्रदेश में लगभग 20 लाख कृषकों ने आवेदन किया है जिन्हें अतिशीघ्र बैंकों द्वारा के.सी.सी. जारी किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अभी भी बड़ी संख्या में लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें किसान क्रेडिट कार्ड जारी नहीं है। ऐसे समस्त कृषकों को सभी हितधारकों द्वारा समंवय स्थापित करते हुए अभियान चलाकर संतृप्त करने के निर्देश दिये गये।**

(कार्यवाही: समस्त बैंक व कृषि विभाग, उ0प्र0)

- आगामी **"ऑनलाइन रोज़गार संगम"** में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विशेष रूचि ली जा रही है। अतः समस्त बैंकों द्वारा अपने समग्र प्रयासों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु प्रयास किये जाने चाहिए।

सभी गणमान्य अतिथियों के सम्बोधन के पश्चात सभा के समक्ष पॉवर प्वाइंट प्रस्तुति दी गयी जिसमें निम्न बिन्दु सामने आए:-

1) कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा डी.बी.टी. के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता राशि प्रदान की रही है जिसके परिणामस्वरूप बैंक मित्र केन्द्रों पर भीड बढ रही है तथा सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करने में कठिनाइयाँ आ रही है। अतः अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त महोदय द्वारा समस्त बैंकों को बैंक मित्रों की संख्या बढाने पर विचार करने हेतु परामर्श दिया गया। बैंक मित्रों की नियुक्ति से अनेक लोगों को रोज़गार प्रदान करने में भी मदद मिलेगी।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

2) प्रदेश के कृषकों को प्रदान किये जा रहे कृषि ऋण की प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु शाखाओं को भूलेख पोर्टल पर ऑनलाइन भूमि बंधक किये जाने की व्यवस्था हेतु शासन से पुनः अनुरोध दोहराया गया।

(कार्यवाही: राजस्व परिषद, उ0प्र0, संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उ0प्र0)

<u>वार्षिक ऋण योजना 2020-21 हेतु लक्ष्य</u>

3) वार्षिक ऋण योजना 2020-21 के लक्ष्य निर्धारण के विषय पर बैठक में विस्तृत चर्चा की गयी। चर्चा के दौरान बैंकों द्वारा कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत वार्षिक ऋण योजना को वास्तविक उपलब्धि के आधार पर निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा गया। अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त, उ0 प्र0 द्वारा यह प्रस्तावित किया गया कि चालू वित्तीय वर्ष हेतु कृषि क्षेत्र के लक्ष्यों को गत वर्ष के लक्ष्यों के सापेक्ष स्थायी रखा जाए तथा एम.एस.एम.ई. के लक्ष्यों का निर्धारण समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धकों से प्राप्त लक्ष्यों के आधार पर ही किया जाए तथा अन्य क्षेत्रों के लक्ष्यों को गत वर्ष की उपलब्धि में 20% की वृद्धि के साथ समस्त बैंकों को आवंटित किया जाए। इस प्रस्ताव पर सभी सम्मानित सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21में कृषि क्षेत्र हेतु रू. 170201.00 करोड़, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु रू. 61759.00 करोड़ तथा अन्य क्षेत्रों हेतु रू. 14790.00 करोड़ के लक्ष्यों के साथ कुल रू. 246750.00 करोड़ का लक्ष्य वार्षिक ऋण योजना 2020-21 हेतु निर्धारित किया गया है। इस प्रकार आवंटित लक्ष्यों में गत वर्ष की उपलब्धि पर लगभग 23% (रू. 45894 करोड़) की वार्षिक वृद्धि परिलक्षित होती है।

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ.प्र. ZONAL OFF (LUCKNOW ZONE) अंचल कार्यालय

4) प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम के 2020-21 के विभाग से प्राप्त 8591 ईकाइयों हेतु रू. 25772.10 लाख मार्जिन मनी के लक्ष्यों को सभा के समक्ष रखा गया जिसे समस्त द्वारा अनुमोदित किया गया।

5) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 शासन ने स्वयं सहायता समूहों के बचत खातों तथा ऋण आवेदन पत्रों के बैंक शाखाओं में अत्यधिक समय तक लम्बित रहने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने अवगत कराया कि शाखा स्तर पर बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह के फार्म बचत खाता खोलने हेतु लम्बित हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी अवगत कराया कि बैंक शाखा स्तर पर स्वयं सहायता समूहों के ऋण आवेदन पत्र बड़ी संख्या में लम्बित हैं। अतः सभी बैंकों से अनुरोध है कि उक्त लम्बित आवेदन पत्रों शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

6) भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार समस्त बैंकों व राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा त्रैमासिक सूचना के ससमय व व्यवस्थित प्रेषण हेतु एक प्रणाली विकसित की जानी है जो चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 से शुरू की जानी प्रस्तावित है। समस्त बैंक से नये प्रणाली पर विस्थापित करने हेतु स्थिति से 28.04.2020 तक अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया था। जिन बैंकों से सूचना प्राप्त नहीं हुई है उनसे पुनः अनुरोध है कि वस्तुस्थिति से हमें व भारतीय रिज़र्व बैंक को शीघ्र हीअवगत कराने का कष्ट करें।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

7) चर्चा के दौरान प्रदेश में वसूली प्रमाण में बढती हुई संख्या पर समस्त बैंकों द्वारा गम्भीर चिंता प्रकट की गयी तथा वसूली प्रमाण पत्रों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु समस्त बैंकों द्वारा राजस्व विभाग, उ0प्र0 के आर.सी. पोर्टल का यूज़र आई.डी. व पासवर्ड सभी बैंकों को प्रदान कराने का अनुरोध संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उ0प्र0 से दोहराया गया।

(कार्यवाही: संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उ.प्र और राजस्व विभाग, उ0प्र0)

8) एजेण्डा पुस्तिका के माध्यम से अवगत कराया गया कि प्रदेश में कुल 75 आरसेटी संस्थान कार्यरत है। आरसेटी संस्थानों के क्रियाकलापो तथा प्रगति समीक्षा हेतु पंजाब नेशनल बैंक के समंवय में एस.एल.बी.सी. की एक उपसमिति गठित है जिसमें विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाती है। प्रदेश के -4- जनपदों यथा बान्दा, रामपुर, प्रयागराज तथा चन्दौली मे आरसेटी हेतु लम्बित है। अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा भवन निर्माण हेतु अंतिम तिथि 30.06.2020 निर्धारित की गयी है। संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उ0प्र0 से अनुरोध है कि उक्त लम्बित प्रकरणों हेतु नोडल एजेंसी से सम्पर्क स्थापित करते हुए भूमि आवंटन की प्रक्रिया अतिशीघ्र पूर्ण कराने का कष्ट करें।

(कार्यवाही : संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उ.प्र; यू.पी.एस.आर.एल.एम.; ग्राम्य विकास विभाग, उ.प्र.)

9) ऋण जमानुपात पर चर्चा करते हुए प्रदेश के ऋण जमानुपात को राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने हेतु समस्त बैंकों द्वारा सघन प्रयास किये जाने पर बल दिया गया विशेष कर ऐसे बैंक जिनका ऋण जमानुपात 40% से कम है यथा सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, यूको बैंक, आई.डी.बी.आई. बैंक, काशी गोमती सम्युत ग्रामीण बैंक व पूर्वांचल ग्रामीण बैंक।

(कार्यवाही : समस्त सम्बन्धित बैंक व यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (संयोजक, ऋण जमानुपात हेतु उप-समिति)

10) प्रदेश में 14 ऐसे जनपद हैं जिनका ऋण जमानुपात 40% से कम है जिनमें यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के 6 जनपद, सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के 4 जनपद, भारतीय स्टेट बैंक तथा बैंक ऑफ बड़ौदा के दो-दो जनपद शामिल हैं। इन जनपदों में समस्त बैंकों द्वारा विशेष प्रयासों की आवश्यकता है।

(कार्यवाही : समस्त सम्बन्धित बैंक व यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (संयोजक, ऋण जमानुपात हेतु उप-समिति)

11) प्रदेश के 10 ऐसे केन्द्र हैं जिन पर उपस्थिति बैंकिंग आउटलेत को डी.बी.टी- जी.आई.एस. पोर्टल पर सम्बन्धित बैंकों अद्यतन किया जाना लम्बित हैं। सम्स्त सम्बन्धित से अनुरोध है कि इस प्रक्रिया को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर लिया जाए।

(कार्यवाही: इलाहाबाद बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, काशी गोमती सम्युत ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया)

बैठक के अंत में **श्री बलबीर सिंह लुथरा, उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0प्र0)** ने समस्त सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

******

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ0प्र0 ZONAL OFF. (LUCKNOW) अंचल कार्यालय (लखनऊ)

List of the participants for SLBC (UP) Meeting dated 05.05.2020

PARTICIPATION SHEET

Sr. No.	Organization	Designated Member	Status of Participation	Participating Authority & Contact Details			Email_ID
				Designation	Name	Contact No.	
1	Bank of Baroda, Corporate Office, Mumbai	Chairman & Managing Director / Executive Director	Yes	Executive Director	Shri Vikramaditya Singh Khichi		
2	Bank of Baroda, Lucknow Zone	Chief General Manager	Yes	Chief General Manager	Dr. Ram Jass Yadav	7379573333	zm.upu@bankofbaroda.com
3	Reserve Bank of India, Lucknow	Regional Director	Yes	Regional Director	Shri R Lakshmi Kanth Rao	9094028645	rlkrao@rbi.org.in
4	NABARD	Chief Gen. Manager	Yes	Chief Gen. Manager	Shri Shankar A Pande		
5				General Manager	Shri R Anand		
6	State Bank of India	Chief Gen. Manager/Gen. Manager	Yes	General Manager	Shri G S Rana	7506094873	gm3.lholuc@sbi.co.in
7	Indian Bank	Field Gen. Manager/ State Head	Yes	General Manager	Shri Ravindra Singh	9815742224	
8	Union Bank of India	Gen. Manager/ State Head	Yes	General Manager	Shri Atul Kumar	9886300111	atulkumar@unionbankofindia.com
9	Bank of India	Gen. Manager/ State Head	Yes	General Manager	Shri Brij Lal	7541813901	nb.north2@bankofindia.co.in
10	Central Bank of India	Field Gen. Manager/ State Head	Yes	General Manager	Shri Narendra Singh	9765552575	zm.luckzo@centralbank.co.in
11	Canara Bank	Chief Gen. Manager/ State Head	Yes	General Manager	Shri Devendra Sahoo	9570333111	coluck@canarabank.com
12				Senior Manager	Shri Vijay Kumar	8756993559	afps.coluck@canarabank.com
13				Senior Manager	Shri M K Mishra	8004912850	zo.lucknow@syndicatebank.co.in
14	Punjab National Bank	Field Gen. Manager/ State Head	Yes	General Manager	Shri Sameer Bajpai	7060081975	sbajpai@pnb.co.in
15	Aryavart Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri S B Singh	9594718299	shiv.singh2@bankofindia.co.in
16	U P Cooperative Bank	Managing Director	No	Chief General Manager	Shri S P Tripathi	9452067232	sptripathide@gmail.com
17				Dy. Gen. Manager	Shri Harsh Gupta	9450002055	upcbidd@gmail.com
18	Finance	Addl. Chief Secretary	Yes	Addl. Chief Secretary	Shri Sanjeev Kumar Mittal, IAS		
19				Special Secretary	Shri C L Gupta	9454412894	
20	MSME	Principal Secretary	Yes	Principal Secretary	Shri Navneet Sehgal, IAS		
21	Rural Development	Secretary	Yes	Secretary	Shri K Ravindra Naik, IAS	8953661111	crd-up@nic.in
22	UPSRLM	Managing Director	Yes	Managing Director	Shri Sujeet Kumar, IAS		
23				JMD	Shri M D Mishra	9415488640	upsrlm7@gmail.com
24				SPM Micro Finance	Shri Deewakar Singh	7897184210	pmmisupsrlm@gmail.com
25				PM- MF/FI	Shri Nishant Singh	9839129579	nishatsingh.upsrlm@gmail.com
26	Directorate of Instt. Finance (DIF)	Director General	Yes	Director General	Shri Shiv Singh Yadav	9415106200	
27	Directorate of Agriculture	Director	Yes	Director Agriculture	Shri Soraj Singh	8429031506	dirag@nic.in
28				JDA (Stat)	Shri Rajesh K Gupta	9450911078	jdastatdas@gmail.com
29	KVIC	State Director	Yes	State Director	Shri S K Mishra	9416410411	skmishra212@gmail.com
30				Asstt. Director	Shri Ashutosh Kr. Singh	9415463417	kvic.lko2011@gmail.com
31	SIDBI	State Head/General Manager	Yes	General Manager	Shri Rajesh D Kale	9892058012	rajeshkale@sidbi.in
32			No	Dy, General Manager	Shri Heera Lal Srivastava	9811201401	hlsrivastava@sidbi.in
33	Police Headquarter	Director General of Police	No	DIG Crime	Shri K B Singh	8004059000	
34				Inspector	Shri R N Chaudhary	9451903726	
35	Matikala Board			Asstt. Director/N.O.	Dr. S K Pandey	9452815470	ddocri@gmail.com
36	UPICO			Managing Director	Shri Pravin Singh	9454833333	pravin.singh@upico.in
37	Bank of Baroda			Dy. General Manager	Shri B S Luthra	0522-6677722	slbc.up@bankofbaroda.com
38				Senior Manager	Shri Brijesh Kumar Gupta	0522-6677730	slbc.up@bankofbaroda.com
39				Senior Manager	Smt. Nitu Shukla	0522-6677717	slbc.up@bankofbaroda.com
40				Manager	Shri Ritesh Rai	0522-6677694	slbc.up@bankofbaroda.com
41				Manager	Shri Ajit Kumar	0522-6677694	slbc.up@bankofbaroda.com
42				Officer	Ms Anjali Singh	0522-6677694	slbc.up@bankofbaroda.com
43				Officer	Ms. Shikha Tripathi	0522-6677726	slbc.up@bankofbaroda.com
44				Business Associates	Shri Arun Kumar Agarwal	0522-6677725	slbc.up@bankofbaroda.com